

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा नरिमति नवीन बाँध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीनी अधिकारियों ने एक चीनी पनविद्युत कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी (जो तबिबत में यारलुंग ज़ान्गबो के नाम से जानी जाती है) के नमिन-प्रवाह में प्रथम 'अनुप्रवाह पनविद्युत परियोजना' (Downstream Hydropower Project) के नरिमाण की अनुमति दे दी है।



प्रमुख बद्दु:

■ ब्रह्मपुत्र:

- इसे उत्पत्ति स्थल पर सियांग या दहिांग के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग (Chemayungdung) ग्लेशियर से है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है।
- सहायक नदियाँ:
- इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दबिांग, लोहति, सियांग, बुढी दहिांग, तीसता और धनसरी हैं।
- यह एक बारहमासी नदी है, जो अपने भूगोल और वशिषिट जलवायु परस्थितियों के कारण अनेक वलिक्षण वशिषिताओं से युक्त है।
- इसमें वर्ष में दो बार बाढ की स्थति रहती है। पहली, गर्मियों में हिमालयी हिम के पघिलने के कारण और दूसरी मानसून के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है।
 - हाल ही में इन बाढों की आवृत्ति बढ गई है। जलवायु परिवर्तन तथा उच्च एवं नमिन प्रवाह के प्रभाव के कारण इन बाढों की वनिाशकता बढ गई है।
 - यह भारत और बांग्लादेश के नचिले राज्यों में जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा के दृषटकिाण से चतिा का वशिषय है।
- नदी की गतशील भूसखलन और भूगर्भीय गतविधियों के कारण प्रायः नदी मार्ग में परिवर्तन देखने को मलिता है।

परियोजना के बारे में:

- चीनी राज्य के स्वामतिव वाली पनविद्युत कंपनी 'पॉवरचाइना' (POWERCHINA) द्वारा नवीन 'पंचवर्षीय योजना' (अवधि 2021-2025) के हसिसे के रूप में यारलुंग ज़ान्गबो नदी के अनुप्रवाह में पनविद्युत के दोहन के लयि 'तबिबत स्वायत्त क्षेत्र' (Tibet Autonomous Region- TAR) सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कयि गए हैं।
 - यह पहली बार होगा जब नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र का दोहन कयि जाएगा। हालाँकि नियोजति परियोजना के स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं

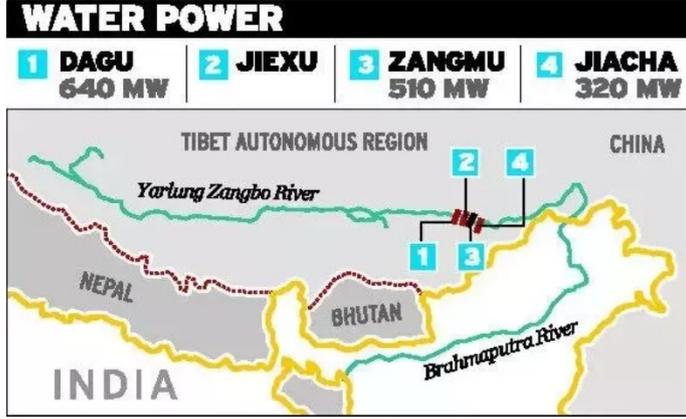
है।

- ब्रह्मपुत्र नदी का 'महान अक्षसंधीय वलन' (ग्रेट बेंड) और मेडोग काउंटी में यारलुंग ज़ान्गबो नदी पर स्थिति 'ग्रैंड कैनयिन' क्षेत्र- जहाँ नदी का बहाव बहुत तेज़ है तथा यह अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, इस परियोजना के लिये संभावित स्थान हो सकता है।

- इस 50 कमी. लंबाई के अकेले खंड में 70 'मलियिन किलोवाट घंटे' (Kwh) की पनवदियुत वकिसति करने की क्षमता है।

चीन की पूर्ववर्ती परियोजनाएँ:

- वर्ष 2015 में चीन द्वारा तबिबत के ज़ान्गमु (Zangmu) में अपनी पहली पनवदियुत परियोजना का संचालन किया गया था, जबकि डागू (Dagu), जिएक्सु (Jiexu) और जियाचा (Jiacha) में तीन अन्य बाँध नरिमति किये जा रहे हैं, जो नदी के ऊपरी और मध्य प्रवाह में हैं।



चीन के लिये परियोजना का महत्त्व:

- 60 मलियिन kWh पनवदियुत के दोहन से प्रतिवर्ष 300 बलियिन kWh स्वच्छ, नवीकरणीय और शून्य-कार्बन उत्सर्जन युक्त वदियुत प्रदान की जा सकती है।
- परियोजना वर्ष 2030 से पहले 'कार्बन उत्सर्जन' के शिखर पर पहुँचने और वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता (शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य) की स्थिति प्राप्त करने के चीन के लक्ष्य को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारत के लिये चिंता का वषिय:

- भारत वर्ष 2015 से- जब चीन ने ज़ान्गमु पर अपनी परियोजना का संचालन शुरू किया था, पर चिंता व्यक्त कर रहा है।
- अगर ग्रेट बेंड में एक बाँध के नरिमाण को मंजूरी दे दी जाती है, तो इसके स्थान को लेकर (जो नदी के अनुप्रवाह और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थिति होगा) भारत द्वारा नई चिंताओं को उठाया जाएगा।
 - इस परियोजना में भारत के लिये जल की मात्रा एक मुद्दा नहीं है क्योंकि ये बाँध 'रन-ऑफ-द-रिवर' प्रकार के हैं और ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।
 - इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मपुत्र पूरी तरह से ऊपरी-प्रवाह (Upstream) पर निर्भर नहीं है। इसके बेसिन का अनुमानित 35% हिस्सा भारत में है।
- हालाँकि भारत, चीनी गतिविधियों के कारण प्रभावित होने वाली जल की गुणवत्ता, पारस्थितिकी संतुलन और बाढ़ प्रबंधन को लेकर चिंतित है।
- भारत और चीन के बीच कोई जल साझाकरण समझौता नहीं है, दोनों देश हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करते हैं। इसलिये वास्तविक डेटा साझा करना और सूखे, बाढ़ तथा भारी मात्रा में जल के नरिवहन की चेतावनी जैसे मुद्दों पर नरितर संवाद करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

आगे की राह:

- भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान-प्रदान से आगे बढ़कर चीन से पूरे बेसिन की स्थलाकृतिक स्थितिके बारे में जानकारी के आदान-प्रदान की मांग करनी चाहिये।
- ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसी भी कदम के लिये दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक समझ की आवश्यकता होगी। भारत के लिये चीन को नरितर वार्ता में शामिल करना एवं जल-साझाकरण संधिको अपनाना दोनों देशों के हितों की रक्षा के दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

स्रोत: द हट्टि

